भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 947
06 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के माध्यम से हासिल प्रगति

947. श्री प्रदीप कुमार वर्माः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 के माध्यम से क्षमता विस्तार और स्क्रैप रीसाइक्लिंग से कच्चे इस्पात का उत्पादन, कच्चे माल की सुरक्षा, संधारणीय विनिर्माण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में क्या प्रगति हुई है;

(ख) एसएआईएल, आरआईएनएल और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों के आधुनिकीकरण के माध्यम से प्रौद्योगिकी उन्नयन, पर्यावरण अनुपालन और परिचालन दक्षता में क्या उपलब्धियां हासिल हुईं हैं;

(ग) विशेष इस्पात और मूल्यसंवर्धित उत्पादों के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रतिस्पर्धा और औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या सुधार हुआ है; और

(घ) हरित इस्पात, हाइड्रोजन-आधारित उत्पादन और कार्बन-तटस्थ लक्ष्यों के माध्यम से सतत उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था में क्या सफलता प्राप्त हुई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग) इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत माहौल सृजित कर सुविधाकर्ता की भूमिका निभाती है। निवेश, क्षमता विस्तार, उत्पादन, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आयात, निर्यात, रोजगार, इस्पात संयंत्र की स्थापना आदि जैसे निर्णय कंपनियों द्वारा प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण के आधार पर लिए जाते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 को सरकार और इस्पात क्षेत्र को नीतिगत दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया था, ताकि एक प्रौद्योगिकी रूप से उन्नत एवं वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी उद्योग का निर्माण किया जा सके, जो आर्थिक विकास को समर्थन दे सके। एनएसपी, 2017 में किए गए अनुमानों की तुलना में विभिन्न मानदंडों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है:-

जारी.....2/

			(मिलियन टन में)
क्रम सं.	**मानदंड**	**एनएसपी, 2017 के तहत वर्ष (2030-31) हेतु अनुमान**	**वर्तमान स्थिति (2024-25)**
1	कुल क्रूड स्टील क्षमता	300	200.33
2	कुल क्रूड स्टील मांग/उत्पादन	255	152.18
3	कुल तैयार इस्पात मांग/उत्पादन	230	146.69
4	प्रति व्यक्ति तैयार इस्पात खपत (किलोग्राम में)	158	108

अप्रैल–दिसंबर 2025 के दौरान तैयार इस्पात का आयात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 37.4% घटकर 7.424 मिलियन टन से 4.649 मिलियन टन हो गया। तैयार इस्पात का निर्यात पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 33.3% बढ़कर 3.6 मिलियन टन से 4.799 मिलियन टन हो गया।

आधुनिकीकरण के माध्यम से, वर्ष 2017 से अब तक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने प्रमुख प्रौद्यो-आर्थिक एवं प्रचालन दक्षता मानदंडों में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है, जिनमें ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता में वृद्धि, कोक दर तथा विशिष्ट ऊर्जा खपत में कमी शामिल हैं।

(घ): सरकार ने सतत इस्पात उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई पहलें की हैं। इनमें ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी की अधिसूचना शामिल है, जिसके अंतर्गत 60 इस्पात इकाइयों को कुल 9.17 मिलियन टन ग्रीन स्टील उत्पादन दर्ज करने सहित प्रमाणित किया गया है तथा वर्ष 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने हेतु रोडमैप ''ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया'' प्रकाशित किया गया है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत इस्पात निर्माण में हाइड्रोजन के उपयोग हेतु पायलट परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जबकि राष्ट्रीय सौर मिशन नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से उत्सर्जन में कमी का समर्थन करता है। पुनर्चक्रण को इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019, पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) की वाहन स्क्रैपिंग नीति, तथा पर्यावरण संरक्षण (प्रयोग अवधि समाप्त वाहन) नियम, 2025 के माध्यम से सुदृढ़ किया जा रहा है, जो मिलकर पर्यावरण-अनुकूल पुनर्चक्रण, सामग्री पुनर्प्राप्ति और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को बढ़ावा देते हैं।

******